ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

भारत में बचत एवं निवेश की प्रवृत्तियों की व्याख्या

Explanation of Savings and Investment Trends In India

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

रामकृत कुमार अरुण
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महोबा, उ0प्र0, भारत

सारांश

भारत देश में प्राचीन काल से ही बचत एवं निवेश की परम्परा चली आ रही है। हमारा प्राचीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा था। प्राचीन काल में हमारे देश में स्वर्ण की एवं चाँदी की मुद्राऐं प्रचलन में थीं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश के लोग बचत एवं निवेश करने की प्रवृत्ति में निपुण थे। जिसके कारण प्राचीन काल में हम बहुत सम्पन्न एवं अर्थ तंत्र में निपुण माने जाते थे। उपभोग पर व्यय नहीं की गयी आय को बचत कहा जाता है। दूसरे शब्दो में जिस आय को उपभोग पर खर्च नहीं किया गया, वह बचत है।

निवेश भौतिक पूँजी पर किया गया व्यय है। लेकिन आम बोल चाल की भाषा में निवेश के अन्तर्गत किसी परिसम्पत्ति की खरीद को सम्मिलित किया जाता है या वस्तुतः प्रारम्भ में त्याग करने का कोई भी वायदा निवेश है। जिससे बाद में लाभ मिलता है। आय निर्धारण के सिद्धान्त में निवेश का अर्थ है पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय। इस अर्थ में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहा जायेगा। इस शोध पत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओंपर तथ्यपूर्ण व्याख्या की जायेगी, जैसे कि कि बचत एवं निवेश, महत्व, बचत एवं निवेश का अर्थ, भारत में बचत की प्रवृत्ति, परिवारिक क्षेत्र की बचत, निजी निगम क्षेत्र की बचत, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत, घरेलू बचत का वर्गीकरण, घरेलू बचत की स्थिति, बचत एवं निवेश दर, बचत की संरचना, आर्थिक समीक्षा, भारत में निवेश की प्रवृत्ति, निवेश की प्रवृत्ति तथा संरचना, संस्थाओं के स्वरूप के अनुसार निवेश, जैसे कि सरकारी संस्था, निजी कार्पोरेट, घरेलू, ग्यारहवीं योजना तथा निवेश (सकल, निजी एवं सार्वजनिक) इन सभी बिन्दुओं पर गहन अध्ययन करके व्याख्या प्रस्तुत की जायेगी। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को सम्मिलित किया जायेगा।

The tradition of saving and investing has been going on in India since ancient times. Our ancient history was very glorious. Gold and silver currencies were in vogue in our country in ancient times. It can be inferred that since ancient times, the people of our country were adept at saving and investing. Due to which in ancient times we were considered very rich and skillful in the economy. Income not spent on consumption is called savings. In other words, income that was not spent on consumption is savings.

Investment is expenditure made on physical capital. But in the language of common parlance, investment involves the purchase of an asset or virtually any futures invested at the outset. Which gives a later benefit. In the principle of income determination, investment means expenditure on capital goods. In this sense, increase in capital stock will be called investment. The following points will be interpreted factually under this research paper, such as savings and investment, importance, meaning of savings and investment, trend of savings in India, family sector savings, private sector savings, public sector savings, household Classification of savings, status of domestic savings, savings and investment rate, structure of savings, economic review, trend of investment in India, trend of investment and structure, investment according to the nature of institutions, such as government institutions, private corporate, domestic, Eleventh Plan and Investment (Gross, Private and Public) All these points will be studied in depth and interpretation will be presented. Small and cottage industries will be included in this.

मुख्य शब्द : प्रवृत्तियाँ, पारम्परिक व्यवहार, उपर्युक्त, परिसम्पत्ति, प्राप्तकर्ता, अर्थशास्त्र, स्वीकार्य, सम्पूर्ण, अनवरत, परिवर्तन, संतुलन, आर्थिक, संगठित, अल्पकालिक, इत्यादि।

Trends, Traditional Practices, Above, Assets, Recipients, Economics, Acceptable, Complete, Continuous, Change, Balance, Economical, Organized, Short term, etc.

प्रस्तावना

भारतीय अर्थ व्यवस्था में बचत एवं निवेश के महत्वपूर्ण स्थान की व्याख्या

भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश की दोहरी भूमिका है। वे समग्र मॉग को प्रभावित करते है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मॉग की भूमिका अल्कालिक उत्पत्ति एवं रोजगार के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। दीर्घकालीन उत्पत्ति में वृद्धि के लिए भी बचत एवं निवेश महत्वूपर्ण है। शायद ही किसी को सन्देह हो कि मुख्यतः घरेलू बचत द्वारा भौतिकएवं मानवीय पूंजी में निवेश कावित्त प्रबन्ध करना आर्थिक विकास की प्रक्रिया निर्णायक होता है। आर्थर लेविस नें 1954 में लिखा था ''आर्थिक विकास के सिद्धान्त की केन्द्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझना है कि जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय का 4 या 5 प्रतिशत बचत एवं निवेश करने वाला समाज अपने को उस समाज में परिवर्तित कर लेता है। जहॉ स्वैच्छिक बचत की राष्ट्रीय आय के 12 या 15 प्रतिशत या अधिक हो जाती है।

भारत में बचत की प्रवृत्ति की व्याख्या

भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का विश्लेषण करते हुए अनेक भारतीय अर्थशास्त्रियों नें ऐसा बताने का प्रयास किया है कि भारत की पारम्परिक निम्न दर पर विकास करती अर्थ व्यवस्था नें 1980 के दशक में आधुनिक उच्च विकास दर के पथ पर पदार्पण किया। इस बदलाव के लिए घरेलू बचत तथा निवेश दर में वृद्धि प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। बचत तथा निवेश का अध्ययन मुख्य रूप से बचत दर तथा निवेश दर की सहायता से किया जाता है। जिसे सकल घरेलू उत्पाद (स0घ0उ0ळक्च) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन दरों की गणना निम्न प्रकार से की जाती हैः–

बचत दर = **कुल बचत X 100**
चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद

निवेश दर= **कुल निवेश X 100**
चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद

घरेलू बचत के तीन प्रमुख स्रोत हैं।

पारिवारिक क्षेत्र की बचत

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से इच बचत को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। वैयक्तिक व्यय योग्य आय का स्तर, भविष्य में इसमें वृद्धि की आशा, विभिन्न आय वर्गों के मध्य इसका वितरण तथा ब्याज दर। भारत में पारिवारिक बचत में परिवार या व्यक्ति की बचत के साथ–साथ सभी अनिबंधित उद्यमों के बचत को भी शामिल किया जाता है। इसलिए भारत में पारिवारिक बचत के निर्धारिका कारकों में उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त निम्न दो कारकों का भी प्रभाव पड़ता है।

1. अनिबन्धित उद्यमों के लाभ।
2. सकल घरेलू उत्पाद में अनिबन्धित उद्यमों का हिस्सा।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पारिवारिक बचत को वित्तीय बचत तथा भौतिक परिसम्पत्ति के रूप में बचत नामक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।

निजी निगम क्षेत्र की बचत

इस क्षेत्र की सकल बचत दो क्षेत्रों से प्राप्त होती है यथा, मूल्य रिजर्व तथा निगमों के अवतरित लाभ। इस बचत के निर्धारक कारक है। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का हिस्सा, इसकी लाभ दर तथा इसकी पूंजी तीव्रता।

सार्वजनिक क्षेत्र की बचत

इस बचत के दो कारक हैं यथा, केन्द्र या राज्य सरकारों की बचत (राजस्व लोक व्यय) तथा लोक उद्यमों की बचत (लाभ)। यदि सरकारी व्कयय सरकार की राजस्व प्राप्ति से अधिक हो, तो सरकार को ऋणात्मक बचत प्राप्त होगी।

भारत में बचत का वर्गीकरण

सकल घरेलू बचत को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यथा, घरेलू निजी बचत तथा घरेलू सार्वजनिक बचत। पारिवारिक बचत तथा निजी निगम की बचत के योग को घरेलू बचत कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत को अलग वर्ग में रखा जाता है। जो घरेलू सार्वजनिक बचत है। इसके तीन घटक हैं। यथा अ– सरकारी प्रशासन की बचत, ब– विभागीय उद्यमों की बचत, स–गैर–विभागीय उद्यमों की बचत।

अध्ययन का उद्देश्य

शोध पत्र का मूल उद्देश्य यह यह है कि भारत देश में स्वतंत्रता के बाद बचत एवं निवेश की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है। भारत में स्वतंत्रता के बाद बचत एवं निवेश में वर्ष–दर–वर्ष लगातार वृद्धि होती आ रही है। बचत एवं निवेश के आंकड़े को प्रस्तुत करना है। जिससे अर्द्धव्यवस्था का आकलन करने में आसानी हो। जिस देश के लोगों में बचत एवं निवेश करने की प्रवृत्ति अच्छी है तो वह देश आर्थिक रूप से उत्तरोत्तर या लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में बचत एवं निवेश के तथ्यों एवं आंकड़ों को प्रस्तुत करना है।

समस्या (Problem):– भारत देश के बचत एवं निवेश के आंकड़ों का तथ्यात्मक प्रस्तुतीकरणः– भारत में बचत की प्रवृत्ति बचत की स्थिति

सकल घरेलू बचत जो 1950–51 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत थी, बढ़कर 2007–08 में 36.8 प्रतिशत हो गयी और उसके बाद क्रमशः घटकर वर्ष 2015–16 में 32.3 प्रतिशत पर आ गयी है। बचत की दर की इस प्रवृत्ति का एक प्रमुख परिणाम यह रहा कि भारतीय आर्थिक वृद्धि का वित्त पोषण मुख्य रूप से घरेलू बचत द्वारा ही हुआ। विदेशी बचत जो विदेशी व्यापार के चालू खाता के घाटे के बराबर होती है कि भूमिका हमारी विकास प्रक्रिया में कम महत्वपूर्ण रही है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1960 तथा 1980 के

दशकों में जब चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत हो गया था, तब देश के सामने भुगतान संतुलन तथा आर्थिक संकट की समस्या खड़ी हो गयी थी।

यदि बचत की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट होगा कि बचत दर में लगातार वृद्धि नहीं हुई है। बीच–बीच में इसे गतिहीनता का भी सामना करना पड़ा है।

चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के बचत 1950–51 में 9.5 प्रतिशत थी। उसमें 2015–16 तक वृद्धि को तालिका 5.1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.1 बचत एवं निवेश दर

वर्ष	बचत दर	निवेश दर	वर्ष	बचत दर	निवेश दर
1950–51	9.5	9.3	2010–11	33.7	36.5
1960–61	11.6	14.3		2011–12 श्रृंखला	–
1970–71	14.3	15.1	2011–12	34.6	39.0
1980–	17.8	19.2	2013–14	32.1	33.8
1990–31	22.9	26.0	2014–15	33.1	34.4
2000–01	23.7	24.3	2015–16	32.3	33.3

Source : Economic Survey 2017–18

पिछले दशकों की तुलना में 1980 के दशक में सकल बचत दर की वृद्धि दर घट गयी। ऐसा दो कारणों से हुआ (1) उपभोक्ता वस्तुओं को बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पारिवारिक बचत की वृद्धि दर घट गयी। शहरीकरण में तेजी से वृद्धि का भी प्रतिकूल प्रभाव पारिवारिक दर पर पड़ा। 1960 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक पारिवारिक बचत के वित्तीय बचत घटक में अत्यन्त तीव्रगति से वृद्धि हुई, क्योंकि 1969 से 14 बड़े बैंको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंको की शाखाओं का विस्तार तेजी से हुआ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय बचत के संग्रहण में सहायता मिली। उसके पश्चात पारिवारिक बचत में वित्तीय बचत बचत का हिस्सा प्रायः स्थिर रहा। किन्तु 1991 से अधिक सुधारों को प्रक्रिया में गति आने के कारण पूँजी बाजार का आधार विस्तृत हो गया। इससे वित्तीय बचत के रूप में पारिवारिक बचत अधिक होने लगी है।निजी निगम क्षेत्र की बचत जो 1950–51 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशथी, 2015–16 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत हो गयी।

निजी निगम क्षेत्र की बचत मुख्य रूप से मूल्य ह्रास रिजर्व तथा निगमों की रक्षा की गयी, आय द्वारा निर्धारित होती है। इसीलिए इस क्षेत्र की बचत दर प्रमुख रूप से सकल घरेलू उत्पाद में निगम क्षेत्र के हिस्से इसकी लाभ दर तथा पूँजी की तीव्रता निर्धारित होती है। 1970 के दशक में इस क्षेत्र की बचत में स्थिर दर से लगातार वृद्धि होती गयी तथा 1990 के दशक में विशेषकर आठवीं योजना काल में इस वृद्धि में तेजी आयी। नौवीं योजना काल में लाभ में कमी होने के कारण निजी निगम क्षेत्र की बचत दर आठवीं योजना काल के ही बराबर रही।

दशवीं योजना के अन्त में निजी निगम क्षेत्र का बचत बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं योजना के प्रारम्भ (2007–08) में इस क्षेत्र की बचत दर बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गयी। यह वृद्धि दर क्रमशः घटते हुए वर्ष (2011–12) में 7.3 प्रतिशत हो गयी। बारहवीं योजना के दौरान नई श्रृंखला 2011–12 के आधार पर वर्ष 2015–2016 में यह दर 11.9 प्रतिशत रही।

देश में बचत की संरचना को तालिका 5.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.2 बचत की संरचना (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	सकल घरेलू बचत			
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सार्वजनिक	योग
1950–51	6.5	0.9	2.1	9.5
1960–61	6.8	1.6	3.2	11.6
1970–71	9.5	1.4	3.4	14.3
1980–81	12.1	1.6	4.1	17.8
1990–91	18.5	2.6	1.8	22.9
2000–01	21.3	3.7	(–)1.3	23.7
2007–08	22.4	9.4	5.0	36.8
2008–09	23.6	7.4	1.0	32.0
2009–10	25.2	8.4	0.2	33.7
2010–11	23.1	8.0	2.6	33.7
2011–12 श्रृंखला				
2011–12	23.6	9.5	1.5	34.6
2014–15	20.5	11.7	0.9	33.1
2015–16	19.2	11.9	1.3	32.3

स्रोतः– आर्थिक समीक्षा 2017–18

समस्या निवारण– बचत

भारत में बचत की प्रवृत्ति की तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा

सार्वजनिक क्षेत्र की बचत 1990 के दशक में 1.6 प्रतिशत थी, वह घटकर 2000 के दशक में 12 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 2007–08 में सरकारी क्षेत्र की बचत दर में सुधार हुआ और यह बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गयी। 2008–09 में सरकारी क्षेत्र की बचत दर में तेजी से निरावट आई और यह 1.0 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। वर्ष 2009–10 में यह घटकर 0.2 प्रतिशत हो गयी। 2010–11 में सुधार हुआ और यह बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में यह दर क्रमशः 1.4 प्रतिशत, 10.9 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत रही। इस तरह सरकारी क्षेत्र के बचत व्यवहार में पर्याप्त उतार–चढ़ाव परिलक्षित होता है। सकल घरेलू उत्पाद में कम सरकारी बचतों के अनुपालन

का कारण गैर विभागीय सरकारी उद्यमों की कम बचतें और सरकारी प्राधिकरणों की वृहत्तर निर्वचतें थीं।

समस्या–भारत में निवेशकी प्रवृत्ति की समस्या

आर्थिक विकास अनेक कारकों की अर्न्तक्रियाओं का परिणाम होता है। उन विकासशील देशों के लिए जहॉ आर्थिक साधनों की कमी होती है। पूँजी निर्माण अर्थात अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता की वृद्धि के लिए सर्वाधिक तहत्वपूर्ण होता है। इसलिए भारतीय योजनाओं में आर्थिक विकास को निवेश कीदर के साथ जोड़ा गया है। भारतीय योजनाएँ वस्तुतः निवेश की योजनाएँ रहीं है।

योजना की निवेश वृद्धि नीति के अन्तर्गत निवेश दर जो 1950–51 में 9.3 प्रतिशत थी। 1960–61 में 14.3 प्रतिशत, 1970–71 में 15.1 प्रतिशत, 1980–81 में 19.2 प्रतिशत तथा 1990–91 में 26.0 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं योजना (2007–12) के अनुसार ऊँची दर पर निवेश तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आठवीं योजना (1992–97) में निवेश की औसत वार्षिक दर 24.4 प्रतिशत रहीं। नौवीं योजना (1997–02) में भी यह दर लगभग 24.4 प्रतिशत ही रही। दशवीं योजना (2002–07) में यह बढ़कर औसतन 32.1 प्रतिशत हो गयी, जबकि दशवीं योजना के अन्तिम वर्ष (2006–07) में यह बढ़कर 35.5 प्रतिशत थी। ग्यारहवीं योजना में यह दर इस प्रकार थीः 2007–08 में 38.1 प्रतिशत, 2008–09 में 34.5 प्रतिशत, 2009–2010 में 36.5 प्रतिशत, 2010–11 में 36.5 प्रतिशत तथा 2011–12 में 38.2 प्रतिशत बरहवीं योजना के दौरमान यह दर वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 38.7 प्रतिशत, 33.8 प्रतिशत, 34.4 प्रतिशत तथा 33.3 प्रतिशत रही।

विगत कुछ वर्षों में देश के निवेश व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है, उसे तालिका 5.3 में आंकड़ों सहित वर्षवार प्रस्तुत किया गया है।

तालिका : 5.3 निवेश की प्रवृत्ति तथा संरचना (स0घ0उ0 का प्रतिशत)

वर्ष	सार्वजनिक निवेश	निजी निवेश	मूल्यवान मदें	कुल निवेश (भूल–चूक समायोजित भूल)
1950–51	2.8	8.1	–	9.3
1960–61	7.1	7.5	–	14.3
1970–71	6.4	8.9	–	15.1
1980–81	9.2	8.9	–	19.2
1990–91	10.6	14.3	–	26.0
2000–01	7.1	16.3	0.7	24.3
2004–05	7.4	23.8	1.3	32.8
2007–08	8.9	28.1	1.1	38.1
2008–09	9.4	24.8	1.3	34.3
2010–11	8.4	26.0	2.1	33.3

2011–12 श्रृंखला

2011–12	7.5	29.2	2.9	39.0
2013–14	7.1	35.5	1.4	33.8
2014–15	6.8	26.1	1.7	34.4
2015–16	1.5	23.9	1.4	33.3

स्रोतः आर्थिकसमीक्षा 2017–18

समस्या निवारण– निवेश

भारत में निवेश की तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा

वर्ष 2004–05 ऐसा विशिष्ट वर्ष रहा, जब पहली बार निवेश दर 30 प्रतिशत से अधिक हो गयी। 2004–05 और 2013–14 के बीच निवेश दर का औसत लगभग 35. 4 प्रतिशत था, जो 2007–08 में 38.1 प्रतिशत के शिखर पर पहुॅच गया था। इस निवेश दर का औसत 2004–05 से 2007'08 की उच्च वृद्धि के काल में 35.3 प्रतिशत तथा 2011–12 तथा 2013–14 के बीच 35.7 प्रतिशत था। 2013–2014 में 33.8 प्रतिशत की निवेश दर इन दो अवधियों की औसत निवेश दर से कमतर है।

वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में निवेश दर क्रमशः34.40 प्रतिशत तथा 33.3 प्रतिशत रही। कुल मिलाकर समीक्षा करने के उपरान्त देखा गया कि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद निवेश के क्षेत्र में प्रगति की है। अब निवेश में कमी एवं स्थिरता दिखाई पड़ रही है। गत तीन वर्षों में।

तालिका 5.4: भारत में संस्थाओं के स्वरूप के अनुसार निवेश (स0घ0उ0 का प्रतिशत)

क्षेत्र	1990–91 से 1999–2000	2000–01 से 2003–04	2004–05 से 2007–08	2008–09 से 2012–2013	2013–14
सरकारी	8.8	6.8	8.1	8.6	8.0
निजी कार्पोरेट	7.0	5.6	13.9	11.1	12.6
घरेलू (पारिवारिक)	8.0	12.1	11.9	14.1	10.7
कुल निवेश	24.3	25.0	35.3	35.5	32.3

स्रोतः– आर्थिक समीक्षा– 2017–18

समस्या निवारण–निवेश

भारत में सरकारी, निजी, कार्पोरेट एवं घरेलू संस्थाओं में निवेश की प्रवृत्ति की तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सीमक्षा या व्याख्या

तालिका से स्पष्ट है कि 1990–91 से 1999–2000 के बीच निवेश दर स0घ0उ0 का 24.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 2004–05 से 2007–08 के बीच 35.3 प्रतिशत हो गया। 2004–05 से 2007–08 के बीच की बढ़ोत्तरी की अवस्था के दौरान समग्र निवेश में अधिकांश बढ़त का कारण निजी कार्पोरेट क्षेत्र के निवेश

हुई बढ़त रही। उसके उपरान्त के वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश दर में आई गिरावट के कारण कुछ निवेश दर में गिरावट आई। निजी कार्पोरेट क्षेत्र के निवेश में वृद्धि 2004–05 से 2007–08 तक की अवधि में विशेष रूप से तीव्र रही, जब इसका औसत वर्तमान कीमतों पर वार्षिक रूप से 48.1 प्रतिशत था। इसकी वृद्धि दर 2008–09 से 2013–14 के बीच गिरावट 3.4 प्रतिशत रह गयी। सरकारी क्षेत्र का निवेश भी जो पूर्णवर्ती अवधि में 23.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। बाद में मंद गति हो गयी। इसके विपरीत पारिवारिक निवेश में वृद्धि 2004–05 से 2007–08 के दौरान वार्षिक औसत 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 से 2013–14 में औसत 23.5 प्रतिशत तक हो गयी। वर्ष 2015–16 में सरकारीक्षेत्र में निवेश दर 7.5 प्रतिशत रही, जबकि निजी क्षेत्र में यह 23.9 प्रतिशत रही।

ग्यारहवीं योजना एवं बारहवीं योजना में निवेश (सकल, निजी एवं सार्वजनिक) की तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक व्याख्या

1990 के दशक में अपनाये गये आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम के फलस्वरूप निजी निवेश पर लगाये गये प्रतिबन्धों में कमी की गयी। जिसके फलस्वरूप निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन हुआ। जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र के निवेश में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। ग्यारहवीं योजना में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में गिरावट चिन्ता का विषय है। कारण यह है कि इसके (सार्वजनिकर निवेश दर में कमी के) कारण नौवीं योजना में कृषि एवं आधारभूत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक निवेश नहीं किया जा सका। दशवीं योजना में इस प्रवृत्ति का उलट जाना स्वागत योग्य परिवर्तन है और ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजना में इसे बरकरार रखने की बात कही गयी है। किन्तु साथ ही सावधान किया गया कि सार्वजनिक निवेश दर में वृद्धि के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यक्षमता में सुधार की भी आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की वृद्धि वस्तुतः प्रोस्ताहित करेगी। इसी उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक निवेश दर को बढ़ाकर 8.0प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। (दशवीं योजना में यह दर 7.1 प्रतिशत थी तथा इस योजना के अन्तिम वर्ष में 7.8 प्रतिशत) ग्यारहवीं योजना के दौरान पॉच वर्षों में बाह्य कारणों से यह दर क्रमशः 8.9 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत, 9.2 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत तथा 7.7 प्रतिशत रही। बारहवीं योजना में प्रारम्भिक चार वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की औसत निवेश दर 7.15 प्रतिशत रही।

निजी क्षेत्र में कृषि, माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्योग (डैडमै) एवं बड़े निजी कारपोरेट क्षेत्र शामिल है। अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निवेश में इनका हिस्सा 77 प्रतिशत है। रोजगार तथा उत्पत्ति में इनका हिस्सा 77 प्रतिशत से और अधिक है। समावेशीकरण विकास के लिए इनके हिस्से में वृद्धि की जरूरत है। विकास के क्षेत्रीय संतुलन के डैडमै की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ग्यारहवीं योजना में निजी निवेश की दर को दशवीं योजना की औसत पर 25.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 28.7 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए ऐसे आर्थिक पर्यावरण का सृजन करना होगा, जिसमें साहस सभी स्तर पर फूल–फले। नये साहसी प्रवेश कर सकें। प्रतिस्पर्द्धा का सृजन हो ताकि इसके माध्यम से कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। इन सबके लिए यह जरूरी है कि सरकारी नीति निवेशकों के अनुकूल लेन–देन लागत कम हो तथा उच्च स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएँ उपलब्ध हों। ऐसे व्यावसायिक वातावरण के अनेक तत्व मौजूद हैं। लाइसेन्स द्वारा नियंत्रण तथा विवेकाधीन स्वीकृति में काफी कमी हो चुकी है। किन्तु नियंत्रित व्यवस्था के अवशेष अब भी मौजूद हैं। सरकारी एजेन्सियों द्वारा बहुल निरीक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। कर प्रणाली का तर्कसंगत होना जरूरी है।

MSMES द्वारा ही अधिकांश नए रोजगार का सृजन होना संभव है। इसलिए आवश्यक है कि विस्तृत होती निजी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने योग्य वित्तीय व्यवस्था भी हो। इससे वित्तीय समावेशीकरण भी सम्भव होगा।

निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजना में कृषि, सिंचाई तथा जल प्रबन्धन तथा सामाजिक एवं आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि पर भी ध्यान दिया गया। इसका अर्थ है कि सार्वजनिक निवेश अब गैर–इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से हटकर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अधिक होगा।

निष्कर्ष

बचत एवं निवेश के सम्बन्ध में

1. हमारे (भारत) देश के लोग आदि काल से बचत एवं निवेश के महत्व को जानते एवं समझते आ रहे हैं। प्राचीन कालमें भारत देश की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि भारत देश को सोने की चिड़िया की उपाधि दी जाती थी।
2. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होने के बाद से लगातार कुछ वर्षों तक बचत एवं निवेश में वृद्धि होती गयी है। सन् 1950–51 से 1990–91 तक लगातार वृद्धि देखी गयी थी। सन् 2000–01 में कुछ कभी देखी गयीथी।
3. सन् 1969 में जब से देश के बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया तब से लगतार बचत एवं निवेश में वृद्धि होती आयी है।
4. बचत एवं निवेश में गत वर्षों में कमी होनेका मूल कारण भृष्टाचार में वृद्धि और बैंको सम्बन्धित घोटाले इत्यादि कारण बचत एवं निवेश में कमी के मूल कारण है।
5. हमारा भारत देश मिश्रित अर्थ व्यवस्था वाला देश है। जिसमें समाजवादी एवं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रित रूप है। इसलिए देश की अर्थ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्वजनिक उद्योग, अर्द्ध सरकारी उद्योग, निजी उद्योग एवं निगमों इत्यादि परसमान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. देश के लघु एवं कुटी उद्योगों पर ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक इन उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक गॉवों से लोगों का

पलायन होता रहेगा। जब गॉव में रोजगार मिलेगा तो लोगों का पलायननहीं होगा।

सुझााव– बचत एवं निवेश के सम्बन्ध में

भारत देश के लोगों के अन्दर बचत एवं निवेश करने की प्रवृत्ति आदिकाल से चल आ रही है। बचत एवं निवेश की प्रवृत्ति भारत देश स्वतंत्र होने क बाद से लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप सभी लोगों का निवेश 100 प्रतिशत सुरक्षित रहेगा। सरकारों द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए कि आप सभी लोग निम्नलिखित उद्योगों में निवेश करसकते हैं। जैसे– सरकारी विभाग, सार्वजनिक, निगम, निजी कम्पनियाँ एवं राष्ट्रीयकृत बैंको या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संस्थान इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। सरकारों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से जनता को सूचित एवं जागृत किया जाना चाहिए। यदि सरकारों द्वारा ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से निवेश में वृद्धि दिखाई देगी। बचत करना तो हमारे देश के लोगों को आदिकाल से आता है। जिसका प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मन्दीकाल के समय दिखाई देता है। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का अधिकांश भाग आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करते हैं। जन संख्या का बहुत बड़ा भाग सरकार की किसी योजना के सहारे नहीं रहता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *व्यावसायिक पर्यावरण– लेखक– डॉ0 जे0पी0 मिश्रा– साहित्य भवन प्रकाशन– आगरा (उ0प्र0)*
2. *व्यावसायिक पर्याकवरण– लेखक– डॉ0 विनय ऋषीश्वर– साहित्य भवन प्रकाशन– आगरा (उ0प्र0)*
3. *व्यावसायिक अर्थशास्त्र– लेखक–डॉ0 अनुपम अग्रवाल– साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उ0प्र0)*
4. *पर्यावरण अध्ययन– लेखक– डॉ0 एच0एस0 मार्ग, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा (उ0प्र0)*
5. *भारतीय अर्थ व्यवस्था– लेखक– डॉ0 बी0एल0 ओझा– साहित्य भवन प्रकाशन आगरा (उ0प्र0)*
6. *अर्थशास्त्र–लेखक– डॉ0 ओझा एवं अग्रवाल– साहित्य भवन प्रकाशन– आगरा (उ0प्र0)*
7. *आर्थिक विश्लेषण के सिद्धान्त– लेखक– डॉ0 अनुपम अग्रवाल– साहित्य भवन प्रकाशन आगरा (उ0प्र0)*
8. *व्यावसायिक पर्यावरण– लेखक– डॉ0 वी0सी0 सिन्हा– साहित्य भवन संजय भवन प्रकाशन आगरा (उ0प्र0)*
9. *अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र–लेखक– डॉ0 बी0सी0 सिन्हा, संजय साहित्य भवन प्रकाशन– आगरा (उ0प्र0)*
10. *उपकार सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन – उपकार प्रकाशन– आगरा (उ0प्र0)*
11. *प्रतियोगिता दर्पण समसामायिकी वार्षिकी– 2018–2019, 2020*
12. *स्नबमदजे सामान्य ज्ञान–स्नबमदजे च्नइसपबंजपवद पटना (बिहार)*
13. *स्नबमदजे भारतीय अर्थ व्यवस्था–स्नबमदजे च्नइसपबंजपवद पटना (बिहार)*
14. *करेन्ट अफेयर्स वार्षिकांक– 2020– प्रयाग प्रकारशन जार्जटाउन प्रयागराज (इलाहाबाद) उ0प्र0*